

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि विजय आर.ए.एस

राजस्व वाद :- 36/2018

तारीख दायर :- 07/08/2018

प्रार्थी :-

1. कन्यादेवी पत्नि कस्तुरराम जी जाति-सीरवी निवासी-नारलाई तहसील-देसूरी जिला-पाली (राज)

प्रतिवादीगण:-

1. हंसाराम पुत्र स्व. चेलाराम सीरवी निवासी-नारलाई तहसील-देसूरी जिला-पाली(राज)
2. रमेश पुत्र हंसारामजी जाति-सीरवी निवासी-नारलाई तहसील-देसूरी हाल मिठास स्वीट्स अलीबाग जिला-रायगढ , महाराष्ट्र
3. पोकरी पत्नि रूपाराम जी जाति-सीरवी निवासी-नारलाई तहसील-देसूरी जिला-पाली (राज)
4. दला गोद पुत्र स्व. पेमाजी जाति- सीरवी निवासी-नारलाई तहसील-देसूरी जिला-पाली (राज)

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :-

5. श्री प्रवीण रावल अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
6. श्री सुधीर श्रीमाली अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
7. अप्रार्थी संख्या 2 से 4 एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक :- 30/7/2019

प्रार्थीनी ने पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वाद संख्या 12/2018 मे न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04/06/2018 को रिव्यू के संबंध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीनी ने उक्त वाद न्यायालय मे बंटवाडा/घोषणा व निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था। जिसमे पत्रावली प्रति वादीगण के नोटिस की तामील, तलबी के स्टेज पर नियत थी।

उक्त पत्रावली राजस्व केम्प ग्राम नारलाई में प्रस्तुत हुई। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रार्थीनी के वाद की सुनवाई एक तरफा की जाकर निर्णय पारित कर दिया। जबकि

  
उपखण्ड अधिकारी  
(पाली)

प्रार्थनी को सुनवाई का पूर्ण मौका नहीं देकर नजरअदाज करते हुए निर्णय पारित किया गया। उक्त त्रुटि पारित निर्णय में होना प्रथम दृष्टयता वाद प्रकरण के अभिलेख से स्पष्ट है जबकि न्यायालय को प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का विवेचन कर प्रार्थनी को सुना जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना था जो नहीं किया गया। प्रार्थनी को वाद में सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनके प्रतिरक्षा के आधारों को नजरअदाज करते हुए अप्रार्थी के मिथ्या आधार पर प्राकृतिक एवम न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित निर्णय को अपास्त कर प्रार्थनी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित कर न्याय प्रदान करावे।

प्रार्थनी ने निवेदन किया कि प्रार्थनी को अपना पक्ष रखने का पूर्ण मौका देकर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन कर एवम साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना प्रार्थनी की अनुपस्थित में ही एक तरफा निर्णय पारित किया गया जो अपास्त योग्य है। अप्रार्थी द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये वो उक्त प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। चूंकि प्रार्थनी का प्रस्तुत वाद पुश्तैनी सम्पति दादा की सम्पति में कोपासनर के तहत अपने हिस्से बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमें न्यायालय को गलत तवज्जो दिलाकर त्रुटिपूर्ण आदेश करवाया एवं जिसे अपास्त कर पूर्ण सुनवाई फरमावे। प्रार्थनी ने निवेदन किया कि राजस्व केम्प में निर्णय पारित किया, जिसमें जिसकी उपस्थिति दर्ज की उनको पक्षकार बनाया है।

वाद संख्या 12/2018 में प्रार्थनी को बिना सुने पारित कर एकतरफा निर्णय का पुनर्विलोकन कर प्रार्थनी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर न्याय प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन याचिका दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 को काफी अवसर देने एवम एव अन्तिम अवसर दिये जाने के पश्चात जबाव प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जबाव का कथन है कि धारा 229 आरटी एक्ट के तहत पुनर्विलोकन की कार्यवाही में मात्र निर्णय में पारित तुच्छ त्रुटि को ही सुधारा जाता है न कि विधि के सिद्धान्तों द्वारा पारित निर्णय को वर्णित आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं जिसमें प्रार्थना पत्र या पुनर्विलोकन याचिका मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाव में बताया कि प्रार्थनी ने अपने पिता के जीवनकाल में गलत वाद पत्र पेश किया था जिसका प्रार्थनी को कोई हक अधिकार नहीं है। न्यायालय ने सही आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध प्रार्थनी ने कोई अपील रिवीजन, अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के अधिवक्ता गण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थनी ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्व केम्प नारलाई में प्रार्थनी के वाद पत्र की सुनवाई में प्रार्थनी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना, बिना सूचना, बिना नोटिस तामील के एक तरफा त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया जाकर वाद खारिज किया गया। जो प्राकृतिक एवम न्याय के सिद्धान्त के विपरित पारित किये गये निर्णय को अपास्त कर प्रार्थनी को प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी  
देसूरी (गाली)

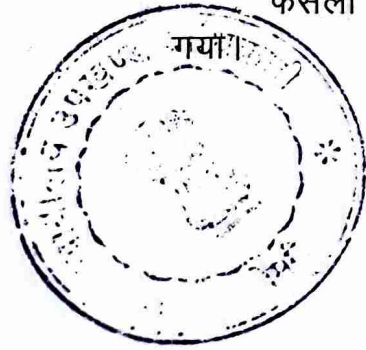
याचिका स्वीकार कर सुनवाई का विधिवत सूचना पूर्ण अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित कर प्रार्थनी को न्याय दिलाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थनी द्वारा धारा 229 आरटी एक्ट के तहत पुनर्विलोकन की कार्यवाही में मात्र निर्णय को पारित कुछ त्रुटि को ही सुधारा जाता है। जिससे प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बहस के सन्दर्भ में Citation 2014 DNJ (SC) पेज 40 प्रस्तुत किया गया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, मूल राजस्व वाद संख्या 12/2018 मय का अवलोकन किया गया। पारित निर्णय दिनांक 04/06/2018 का भी गम्भीरता पूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया गया। प्रकरण में सलग्न प्रार्थनी को जारी सम्मन अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थनी कन्या देवी पत्नी कस्तूरराम जी जाति-सीरवी निवासी-नारलाई के नाम न्यायालय द्वारा दिनांक 04/05/2018 को जारी सम्मन/नोटिस में ग्राम पंचायत नारलाई में दिनांक 04/06/2018 को उपस्थित होने की सूचना है। प्रार्थनी का नोटिस अदम तामील प्राप्त होना जाहिर है। न्यायालय द्वारा पुनः प्रार्थनी को पुन नोटिस जारी करना चाहिए था जो जारी नहीं कर वादीनी कन्यादेवी की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर तथा प्रतिवादी संख्या सं. 1,4,6,7 की उपस्थिति बताई जाकर वादीनी का प्रस्तुत वाद खारिज किया जाना जाहिर होता है। जबकि पत्रावली प्रथमतः नोटिस जारी व तामील के स्टेज पर नियत थी। प्रकरण में प्रार्थनी को पुनः नोटिस जारी कर सूचित किया जाकर आगामी तारीख पेशी दी जानी थी। जो नहीं दी गई तथा वाद खारिज कर दिया गया।

अतः वाद में न्यायालय द्वारा उक्त प्राथमिक स्टेज पर ही प्राकृतिक एवम नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरित प्रार्थनी को सूचित किये बिना जारी नोटिस के प्रार्थनी/वादीनी की अनुपस्थिति बताई जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया जाना "कानूनी त्रुटि प्रकट होना प्रतीत होता है"। जो कि आर.टी एक्ट की धारा 229 के बिन्दू संख्या 35 (REVIEW WHEN PERMISSIBLE) के परिपेक्ष्य में आने से वादीनी/प्रार्थनी की पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 229 आरटी एक्ट व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। एवम वाद संख्या 12/2018 में पारित एक तरफा निर्णय दिनांक 04/06/2018 में प्रार्थनी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनर्विलोकन के आदेश दिये जाते हैं। एक तरफा निर्णय 04/06/2018 अपास्त किया जाता है प्रकरण संख्या 12/2018 पुन दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

फैसला आज दिनांक 30.07.2019 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इज्लास में सुनाया



~~उपस्थित अधिकारी~~  
देवेंद्र (सही)